विवरण

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत 1984-85 से 1986-87 तक विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई राशि

राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (केन्द्रीय हिस्सा)		
	1984-85	1985-86	1986-87*
1. आन्ध्र प्रदेश	378.58	373.27	229.2765
2. असम	26.59	7.15	29.3080
3. बिहार	17.00	29.98	36.0565
4. गुजरात	387.70	436.96	180.9000
5. हरियाणा	11.66	27.15	133.0370
6. हिमाचल प्रदेश	4.50	4.42	3.9600
7. कर्नाटक	219.24	171.68	117.9300
8. उड़ीसा	106.55	132.00	61.700
9. उत्तर प्रदेश	146.68	142.36	94.8650
10. महाराष्ट्र	341.91	489.29	159.3500
11. तमिलनाडु	408.51	444.00	150.6400
12. पंजाब	31.68	9.57	26.8800
13. राजस्थान	123.32	80.55	51.8260
14. मध्य प्रदेश	428.34	274.32	92.6760
15. पश्चिम बंगाल	32.66	24.08	29.6500
16. सिक्किम	0.60	1.82	3.6800
17. जम्मु व काश्मीर	3.00	1.52	2.5150
योग :	2678.52	2648.12	1404.350

* केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर व्यय बांटने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के आरम्भ किये जाने के कारण 1986-87 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि पिछले वर्षों की तुलना में कम थी।

यमुनापार की बस्तियों में अस्वास्थ्यकर स्थिति

3195. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की यमुनापार की बस्तियों जैसे गौतमपुरी, जगजीत नगर और सीलमपुर में सफाई कर्मचारियों द्वारा गंदगी, मैला और कूड़े के ढेरों को न उठाये जाने के कारण वहां के लोग अपनी-अपनी नालियों की सफाई नहीं करा पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समय-समय पर इन कूड़े के ढेरों को न उठाये जाने

के क्या कारण हैं और क्या इन बस्तियों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन कालोनियों में कूड़ाकर्कट प्रतिदिन उठाया जाता है तथा नालियां भी नियमित रूप से साफ की जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण

3196. **श्री केशव प्रसाद शुक्ल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि आदानों के लिए विभिन्न राज्यों को अल्पकालीन ऋण प्रदान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक को उपलब्ध कराये गये ऋण की वर्षवार राशि कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या यह ऋण राज्यों की आवश्यकता के अथवा उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों को खरीफ और रबी मौसमों के लिए पृथक्-पृथक् कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाइयों के वितरण के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। राज्यों को अल्पावधि ऋण सहायता की निर्मुक्ति के लिए उपलब्ध निधि उनकी मांग की तुलना में कम होने के कारण, अधिकतर राज्यों के संबंध में समूची मांग पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान स्वीकृत किये गए अल्पावधि ऋण का ब्यौरा और प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि उपाबन्ध में दी गई है [देखिये परिशिष्ट CXLIII, अनुपत्र सं० 123]

Revamping and renovation of fertilizer plants of HFC

3197. SHRI BASUDEB MOHAPATRA:

KUMARI SUSHILA TIRIA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Fertilizer Corporation had recently submitted Rs. 250 crores plan to revamp and renovate all its three units in Durgapur, Barauni and Namrup;

(b) if so, what steps Government have taken on the said persons; and

(c) what was the accumulated loss suffered by these three units by the end of 1986-87?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Yes, Sir.

(b) Government has decided to get conducted and end-to-end survey of these three units.

(c) The accumulated loss of these three units upto 31st March, 1987 was Rs. 544.66 crores.

Transfers of C.P.W.D. executive engineers

3198. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that transfer orders in respect of various Executive Engineers of C.P.W.D. were